International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 7 Issue 11, November 2017,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

छत्तीसगढ़ राज्य में मनरेगा कार्यक्रम से उत्पन्न रोजगार की प्रवृत्तियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन

* प्रवीण कुमार चन्द्राकर
** ओमप्रकाश बघेल

सार – भारत सरकार द्वारा ग्रामीण भारत में रोजगार की दिशा में कई रोजगार मूलक कार्यक्रम चलाया गया है। जिससे ग्रामीण क्षेत्रो में रोजगार के नए–नए अवसर उत्पन्न हो सके और उनमें से एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम (मनरेगा) है। यह देश के ग्रामीण क्षेत्रो में रोजगार का एक अधिकार आधारित कार्यक्रम है। जिसकी शुरुआत 2 फरवरी 2006 से आंध्रपदेश के अनंतपुर जिले से की गई। प्रस्तुत शोध अध्ययन द्वितीयक आकड़ो पर आधारित है। अध्ययन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य का चुनाव किया गया है, जहां मनरेगा कार्यक्रम प्रथम चरण में राज्य के 11 जिलो में अधिसूचित किया गया था।

शब्द कुंजी – मनरेगा कार्यक्रम, रोजगार, रोजगार की प्रवृत्ति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाएं, भागीदारी, औसत रोजगार ।

प्रस्तावना –

वर्तमान वैश्विक अर्थव्यवस्था चाहे विकसित हो या विकासशील गरीबी एवं बेरोजगारी का पाया जाना एक सामान्य सी बात है। हर समय देश में बड़ी संख्या में अकुशल श्रमिको के साथ–साथ प्रशिक्षण प्राप्त कुशल श्रमिक भारी संख्या में बेरोजगार होते है। बेरोजगारी से देश में गरीबी बढ़ती है और अर्थव्यवस्था का विकास नही हो पाता है। वर्तमान में भारत विश्व में एक मजबूत आर्थिक शक्ति के रुप में उभर रहा है विभिन्न अंतराष्ट्रीय संस्थाओं की रिपोर्ट यह सूचित करती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की 10 वृहद अर्थव्यवस्थो में सम्मिलित हो चुकी है। चाहे औद्योगिक उत्पादन दर हो या वार्षिक वृद्धि की दर इन सभी में निरंतर वृद्धि की प्रवृति रही है, परन्तु भारतीय अर्थव्यस्था के समक्ष सबसे जटिल समस्या ग्रामीण क्षेत्रो में पूर्ण रोजगार प्राप्त करना रहा है। इसका प्रमुख कारण भारत की अधिकांश जनसंख्या गांवो में निवास करती है। जिसका मुख्य व्यवसाय कृषि है। देश की बढ़ती हुई जनसंख्या प्रति वर्ष श्रमशक्ति में वृद्धि करती है और जिस दर से जनसंख्या बढ़ती है उस दर से रोजगार के अवसरो में वृद्धि नहीं होती है। भारत सरकार के द्वारा ग्रामीण भारत में रोजगार की दिशा में कई रोजगार मूलक कार्यक्रम चलाया गया है। जिससे ग्रामीण क्षेत्रो में रोजगार के नए–नए अवसर उत्पन्न हो सके और उसमें से एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम (मनरेगा) है।

* शोधार्थी, अर्थशास्त्र अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

* * शोधार्थी, अर्थशास्त्र अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 7 Issue 11, November 2017,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

जिसे 23 अगस्त 2005 को पारित किया गया तथा 7 सितम्बर 2005 को इसकी अधिसूचना जारी की गई । यह देश के ग्रामीण क्षेत्रो में रोजगार का एक अधिकार आधारित कार्यक्रम है। जिसकी शुरुआत 2 फरवरी 2006 से आंध्रप्रदेश के अनंतपुर जिले से की गई। इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रो में निवासरत प्रत्येक ग्रामीण परिवारो जिनके व्यस्क सदस्य स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक श्रम करना चाहते है, उन्हें एक वित वर्ष में कम से कम 100 दिनो (छत्तीसगढ़ में 150 दिन) का गांरटीशुदा मजदूरी रोजगार उपलब्ध करते हुए आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है। प्रथम चरण में इसे देश के 200 सबसे पिछड़े जिलो (छ.ग. के 11 जिले) में कार्यान्वित किया गया और 1 अप्रैल 2007 से और 130 जिलो (छ.ग. के 4 जिले) में इसका विस्तार किया गया तथा 1 अप्रैल 2008 से देश के शेष जिलो को भी इस कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के सभी 27 जिलो मे मनरेगा कार्यक्रम चल रही है।

अध्ययन का उद्देश्य –

1. छत्तीसगढ़ राज्य में मनरेगा कार्यक्रम के तहत ग्रामीण परिवारो द्वारा रोजगार की मांग एवं प्रदान किये गये रोजगार का अध्ययन करना।
2. छत्तीसगढ़ राज्य में कार्यक्रम के अंतर्गत कुल सृजित रोजगार में अनुसूचित जाति, जनजाति व महिलाओ की भागीदारी का अध्ययन करना।
3. छत्तीगढ़ राज्य में मनरेगा कार्यक्रम के अंतर्गत 100 दिनो का रोजगार प्राप्त करने वाले परिवारो का अध्ययन करना।
4. छत्तीसगढ़ राज्य में मनरेगा कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण परिवारो को प्रदान किये गए औसत रोजगार का अध्ययन करना।

शोध प्रविधि –

प्रस्तुत शोध अध्ययन द्वितीयक आंकड़ो पर आधारित है। अध्ययन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य का चुनाव किया गया है जहां मनरेगा कार्यक्रम प्रथम चरण में राज्य के 11 जिलो में अधिसूचित किया गया था। अध्ययन की अवधि वित वर्ष 2006 –07 से 2015–16 तक 10 वर्षो तक ली गई है। आंकड़े मुख्यतः ग्रामीण विकास मंत्रालय मनरेगा कार्यक्रम की अधिकारिक वेबसाईट www.mgnrega.nic.in द्वारा एकत्रित किय गए है। आंकड़ो के विश्लेषण के लिए औसत, प्रतिशत, वृद्धि दर का प्रयोग किया गया है।

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 7 Issue 11, November 2017,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

अध्ययन का विश्लेषण –

ग्रामीण परिवारो द्वारा रोजगार की मांग एवं प्राप्त रोजगार –

तालिका क्रमांक –1 में छत्तीसगढ़ राज्य में ग्रामीण परिवारो द्वारा मनरेगा कार्यक्रम के अंतर्गत किये गए रोजगार की मांग तथा उन्हें प्रदान किये गये रोजगार को स्पष्ट किया गया है –

तालिका क्रमांक – 1

ग्रामीण परिवारो द्वारा रोजगार की मांग एवं प्रदान किए गए रोजगार

वित्त वर्ष	रोजगार की मांग	प्रतिशत वृद्धि / कमी	प्रदान किए गए रोजगार	प्रतिशत वृद्धि / कमी	मांग अनुसार प्रदान किये गये रोजगार का प्रतिशत
2006–07	1412643	–	1375802	–	97.39
2007–08	2297042	62.60	2284963	66.10	99.47
2008–09	2271194	–1.12	2270415	–0.60	99.96
2009–10	2025845	–10.80	2025845	–10.80	100.00
2010–11	2485581	22.70	2485581	22.70	100.00
2011–12	2737452	10.10	2727371	9.70	99.63
2012–13	2726377	–0.40	2626054	–3.70	96.31
2013–14	2749242	–0.80	2511680	–4.40	91.35
2014–15	2041857	–25.70	1744544	–30.50	85.43
2015–16	2490255	22.00	1877457	7.60	75.39
वृद्धि दर	76.28	–	36.46	–	–

Source ; DMU Reports, www.mgnrega.nic.in

तालिका के विश्लेषण के पश्चात यह ज्ञात होता है कि राज्य में मनरेगा कार्यक्रम के अंतर्गत जिन परिवारो ने रोजगार की मांग की उनमें से 95 प्रतिशत से अधिक परिवारो को रोजगार प्रदान किया गया है। वित वर्ष 2013–14 से 2015–16 के दौरान मांग अनुसार प्रदान किए गए रोजगार के प्रतिशत में कमी की प्रवृत्ति रही है। वित वर्ष 2006–07 से 2015–16 के दौरान राज्य के ग्रामीण परिवारो द्वारा रोजगार की मांग में वृद्धि दर 76.28 प्रतिशत रही , परन्तु परिवारो को इस दौरान प्रदान किए गए रोजगार में वृद्धि की दर 36.46 प्रतिशत ही रही है।

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 7 Issue 11, November 2017,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

कुल सृजित रोजगार में अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग की भागीदारी –

तालिका क्रमांक –2 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में मनरेगा कार्यक्रम के अंतर्गत कुल सृजित रोजगार में अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग की भागीदारी को प्रदर्शित किया गया है।

तालिका क्रमांक – 2

कुल सृजित रोजगार में अनुसूचित जाति व जनजातियों की भागीदारी

वित्तवर्ष	कुल सृजित रोजगार (लाख में)	प्रतिशत वृद्धि / कमी	अनुसूचित जाति (लाख में)	प्रतिशत वृद्धि / कमी	अनुसूचित जनजाति (लाख में)	प्रतिशत वृद्धि / कमी
2006–07	700.21	–	84.08 (12.01)	–	318.98 (45.55)	–
2007–08	1316.10	87.95	196.29 (14.90)	133.45	544.77 (41.39)	70.78
2008–09	1243.18	–5.54	203.97 (16.41)	3.91	513.65 (41.32)	–5.71
2009–10	1041.57	–16.21	159.59 (15.32)	–21.75	397.85 (38.20)	–22.54
2010–11	1110.35	6.60	161.76 (14.57)	1.35	405.43 (36.51)	1.90
2011–12	1212.89	9.23	116.75 (9.63)	–27.82	455.53 (38.17)	12.35
2012–13	1182.90	–2.47	107.27 (9.07)	–8.11	451.56 (38.17)	–0.87
2013–14	1297.01	9.64	115.73 (8.92)	7.88	516.09 (39.79)	14.29
2014–15	554.08	–57.28	59.97 (10.82)	–48.18	177.13 (31.97)	–65.67
2015–16	690.27	24.57	56.74 (8.22)	–5.38	301.09 (43.62)	69.98
वृद्धि दर	–1.41	–	–32.51	–	–5.60	–

नोट– कोष्ठक में दी गई संख्या कुल सृजित रोजगार में से प्रतिशत है ।

Source ; DMU Reports, www.mgnrega.nic.in

तालिका के विश्लेषण के उपरान्त यह स्पष्ट होता है कि मनरेगा कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तवर्ष 2006–07 से 2015–16 के दौरान कुल सृजित रोजगार में –1.41 प्रतिशत कमी की प्रवृत्ति रही है। कार्यक्रम के अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग की भागीदारी में वित्त वर्ष 2006–07 से 2008–09 तक

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 7 Issue 11, November 2017,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

वृद्धि की प्रवृत्ति रही तथा वित्त वर्ष 2009–10 से 2013–14 तक कमी की प्रवृत्ति देखने को मिली है, वहीं दूसरी ओर अनुसूचित जनजाति वर्ग की भागीदारी वित्त वर्ष 2006–07 से 2010–11 के दौरान घटी तथा वित्त वर्ष 2011–12 से 2013–14 के दौरान वृद्धि की प्रवृत्ति रही है। वित्त वर्ष 2006–07 से 2015–16 के दौरान कुल अनुसूचित जनजाति वर्ग को प्रदान किए गए रोजगार में –5.60 प्रतिशत कमी की प्रवृत्ति रही तथा इस अवधि में अनुसूचित जाति वर्ग को प्रदान किये गए रोजगार में कमी की प्रवृत्ति –32.51 प्रतिशत रही।

महिलाओ की भागीदारी –

मनरेगा अधिनियम 2005 की धारा 4(1) के अनुसार इस कार्यक्रम में एक तिहाई महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार के लिए शामिल किया जाना है। तालिका क्रमांक –3 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में मनरेगा कार्यक्रम के अंतर्गत कुल सृजित रोजगार में महिलाओ की भागीदारी को स्पष्ट किया गया है।

तालिका क्रमांक – 3

कुल सृजित रोजगार में महिलाओ की भागीदारी (लाख में)

वित्तवर्ष	महिलाएं	प्रतिशत वृद्धि / कमी	भागीदारी का प्रतिशत
2006–07	275.29	–	39.32
2007–08	553.42	101.03	42.05
2008–09	589.69	6.55	47.43
2009–10	512.53	–13.08	49.21
2010–11	539.96	5.35	48.63
2011–12	548.83	1.64	45.25
2012–13	555.15	1.15	16.93
2013–14	629.42	13.37	48.53
2014–15	276.43	–56.08	49.89
2015–16	335.75	21.45	48.64
वृद्धि दर	21.96	–	–

Source : DMU Reports, www.mgnrega.nic.in

तालिका के विश्लेषण करने से यह स्पष्ट होता है कि छत्तीसगढ़ राज्य में मनरेगा कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओ की भागीदारी एक तिहाई मात्रा से कहीं अधिक है और यह राज्य में महिला

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 7 Issue 11, November 2017,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

सशक्तिकरण के लिए एक अच्छा संकेत है। राज्य में वित्त वर्ष 2006–07 से 2015–16 के दौरान कार्यक्रम के तहत महिलाओ को प्रदान किये गये रोजगार में वृद्धि की दर 21.96 प्रतिशत रही है।

100 दिनो का रोजगार एवं प्रति परिवार औसत रोजगार –

छत्तीसगढ़ राज्य में मनरेगा कार्यक्रम के अंतर्गत 100 दिनो का रोजगार पूर्ण करने वाले परिवारो की संख्या एवं कार्यक्रम के तहत प्रति परिवार प्रदान किये गये औसत रोजगार की स्थिति को तालिका क्रमांक– 4 में प्रदर्षित किया गया है –

तालिका क्रमांक –4

100 दिनो का रोजगार पूर्ण करने वाले परिवारो की संख्या एवं प्रति परिवार औसत रोजगार

वित्तवर्ष	100 दिनो का रोजगार प्राप्त परिवारो की संख्या	प्रतिशत वृद्धि / कमी	प्रति परिवार औसत रोजगार	प्रतिशत वृद्धि / कमी
2006–07	130302 (9.47)	-	50.89	-
2007–08	256071 (11.20)	69.52	57.60	13.18
2008–09	251674 (11.08)	-1.71	54.76	-4.93
2009–10	160851 (7.93)	-36.08	51.41	-6.11
2010–11	184497 (7.42)	14.70	44.67	-13.11
2011–12	215395 (7.89)	16.74	44.47	-0.44
2012–13	239043 (9.10)	10.97	45.04	1.28
2013–14	345253 (13.74)	44.43	51.64	14.65
2014–15	47549 (2.72)	-86.22	31.76	-38.49
2015–16	117605 (6.26)	147.33	36.77	15.77
वृद्धि दर	-9.74	-	-27.74	-

नोट – कोष्ठक में दी गई संख्या परिवारो को प्रदान किए गए रोजगार की संख्या में से प्रतिशत है

Source : DMU Reports, www.mgnrega.nic.in

तालिका क्रमांक–4 के विश्लेषण के पश्चात यह ज्ञात होता है कि राज्य में मनरेगा अधिनियम 2005 में कही गई बातो को जमीनी स्तर पर लागू करने में पूर्णता असफल रही है और 100 दिनो का रोजगार मनरेगा कार्यक्रम के तहत बहुत ही कम परिवारो को दिया जा रहा है। वित्त वर्ष 2006–07 से 2015–16 के दौरान 100 दिनो का रोजगार प्राप्त परिवारो की संख्या में –9.74 प्रतिशत कमी की प्रवृत्ति देखी जा सकती है। राज्य में कार्यक्रम के अंतर्गत परिवारो को प्रदान किये गये औसत रोजगार 100 दिनो के रोजगार के सापेक्ष में बहुत कम है और वित्त वर्ष 2006–07 से 2015–16 के दौरान प्रति परिवार औसत रोजगार में कमी की प्रवृत्ति रही है। इसका मुख्य कारण राज्य में कार्यक्रम के अंतर्गत निरन्तर कार्य का अभाव व प्रशासनिक अधिकारियो की उदासीनता रही है।

निष्कर्ष –

1. राज्य में वित्त वर्ष 2006–07 से 2015–16 के दौरान ग्रामीण परिवारो में रोजगार की मांग में वृद्धि दर 76.28 प्रतिशत रही, परन्तु प्रदान किये गये रोजगार में वृद्धि दर 36.46 प्रतिशत रही है ।
2. राज्य में मनरेगा कार्यक्रम के तहत अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग को प्रदान किये गए रोजगार में क्रमशः –32.51 प्रतिशत व –5.60 प्रतिशत कमी की प्रवृति रही ।
3. छत्तीसगढ़ राज्य में मनरेगा कार्यक्रम के अंतर्गत वित्त वर्ष 2006–07 से 2015–16 के दौरान महिलाओ को प्रदान किये गए रोजगार में वृद्धि दर 21.96 प्रतिशत रही है।
4. वित्त वर्ष 2006–07 से 2015–16 के दौरान 100 दिनो का रोजगार प्राप्त परिवारो की संख्या में –9.74 प्रतिशत कमी की प्रवृत्ति रही और साथ ही इन अवधि में प्रति परिवार औसत रोजगार की प्रवृत्ति भी नकारात्मक रही है । इसका मुख्य कारण राज्य में कार्यक्रम के अंतर्गत निरन्तर कार्य का अभाव व प्रशासनिक अधिकारियों की उदासीनता रही है।

संदर्भ –

1. गौतम, नीरज कुमार, ''ग्रामीण रोजगार और लघु एवं कुटीर उद्योग'' कुरुक्षेत्र अक्टूबर 2014, वर्ष 60 अंक 12, पृ.क्र. 48–52
2. चन्द्राकर, प्रवीण कुमार, ''महासमुन्द जिले में मनरेगा – एक आर्थिक अनुशीलन (ग्राम पंचायत सिंघनपुर के विशेष संदर्भ में)'' अप्रकाशित लघु शोध प्रबंध 2013, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर (छ.ग.)।
3. चन्द्राकर, प्रवीण कुमार एवं अन्य,''महासमुन्द जिले में मनरेगा कार्यक्रम का कियान्वयन–एक मूल्यांकन(वित्त वर्ष 2009–10 से 2015–16 तक)'' रिसर्च जनरल आफ सोशल एण्ड लाइफ साइन्सेस , वर्ष 10, जून 2016, हिन्दी संस्करण, पृ.क्र.61–69 रींवा (म.प्र.)।
4. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजबार गांरटी अधिनियम 2005, वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन 2007–08 से

2012–13, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन।

5. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार महात्मा गांधी नरेगा की अधिकारिक वेबसाइट www.mgnrega.nic.in